

प्रेषक,

मंजुल कुमार जोशी,  
अपर सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निबन्धक,  
सहकारी समितियाँ,  
उत्तराखण्ड।

सहकारिता, गन्ना एवं चीनी अनुभाग:-1 देहरादून दिनांक 04 अक्टूबर, 2010

विषय:- राज्य के जनपद-बागेश्वर, चम्पावत, रुद्रप्रयाग तथा उत्तरकाशी में एकीकृत सहकारी विकास परियोजना लागू किये जाने के लिये डी0पी0आर0 के शुल्क भुगतान हेतु वर्ष 2010-11 में एकीकृत सहकारी विकास परियोजना के अन्तर्गत वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या:-2547/48/नियो0/आईसीडीपी0/2010-11 दिनांक 07 अगस्त, 2010 एवं राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, के पत्र संख्या-स0रासविनि:3-29(11)/2010-आईसीडीपी(162)(SA00077) दिनांक 02 अगस्त, 2010, पत्र संख्या-स0रासविनि:3-29 (11)/2010-आईसीडीपी(161)(SA00077) दिनांक 02 अगस्त, 2010 पत्र संख्या- स0रासविनि:3-29 (11)/2010-आईसीडीपी (163) (SA00077) दिनांक 02 अगस्त, 2010 तथा पत्र संख्या-स0रासविनि:3-29(11)/2010 -आईसीडीपी(160)(SA00077) दिनांक 02 अगस्त, 2010 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद बागेश्वर, चम्पावत, रुद्रप्रयाग तथा उत्तरकाशी में प्रति जनपद ₹ 2.10 लाख की दर से कुल ₹ 8.40 लाख की लागत से प्रश्नगत चार जनपदों के लिये एकीकृत सहकारी विकास परियोजना की डी0पी0आर0 तैयार कराने के लिये तथा सम्बन्धित संस्था को 35 प्रतिशत अग्रिम धनराशि के भुगतान हेतु ₹ 2,94,000/- (दो लाख चौरान्चे हजार मात्र) की धनराशि आपके निर्वर्तन पर रखने हेतु श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। उक्त धनराशि की शत प्रतिशत प्रतिपूर्ति राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा राज्य सरकार को की जायेगी। उक्त स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन है:-

(1) उक्त वित्तीय स्वीकृति इस शर्त के अधीन है कि स्वीकृत धनराशि के उपयोग की मदवार/लक्ष्यवार अद्यतन वित्तीय/भौतिक प्रगति शासन को त्रैमासिक रूप से उपलब्ध करायी जायेगी तथा परियोजना का क्रियान्वयन समयबद्ध आधार पर सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) स्वीकृत धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार किया जायेगा और यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इस योजना के अन्तर्गत अब तक स्वीकृत सभी ऋणों की प्रतिपूर्ति हो चुकी है और उसे कोषागार के सम्बन्धित लेखाशीर्षक में जमा कर दिया गया है।

(3) स्वीकृत अंशपूजी, ऋण एवं अनुदान की धनराशि, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा मूल रूप में स्वीकृत परियोजना में उल्लिखित शर्तों/मदों/लक्ष्यों के अनुसार व्यय की जायेगी।

(2)

(4) स्वीकृत धनराशि, निगम की परियोजना के अनुरूप राज्य सरकार द्वारा वर्तमान में व समय समय पर प्राप्त शर्तों के अनुरूप नियंत्रित होगी तथा एन0सी0डी0सी0 के पत्र दिनांक 20 जनवरी, 2010 व उपरोक्त संदर्भित पत्रों द्वारा निर्गत दिशानिर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(5) इन शर्तों के अनुपालन व परियोजना की प्रगति को सुनिश्चित किये जाने की पूर्ण जिम्मेदारी निबन्धक, सहकारी समितियां उत्तराखण्ड की होगी

(6) आवश्यक उपयोगिता प्रमाणपत्र एवं इसकी सूचना यथासमय राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को तथा राज्य सरकार को त्रैमासिक रूप से अवगत कराना होगा और पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित होने के उपरान्त ही अवशेष धनराशि के उपयोग की कार्यवाही की जानी होगी।

2. इस शासनादेश के प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि किसी अन्य प्रयोजन के लिये प्रयोग में नहीं लाई जायेगी। अवमुक्त धनराशि के व्यय का लेखा परीक्षण नियमानुसार किया जायेगा तथा महालेखाकार उत्तराखण्ड द्वारा भी किया जा सकता है। प्रस्तर-1 में निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन विभागों/उपक्रमों में तैनात वित्त नियंत्रक/मुख्य लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे।

3- उपर्युक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2010-11 के आय व्ययक में सहकारिता विभाग से सम्बन्धित अनुदान संख्या-18 के अन्तर्गत निम्नलिखित लेखाशीर्षक/मद के नामें डाला जायेगा:-

(धनराशि ₹ हजार में)

लेखाशीर्षक	बजट प्राविधान	अवमुक्त धनराशि
2425- सहकारिता-आयोजनागत		
00-		
800- अन्य व्यय		
04- एकीकृत सहकारी विकास परियोजना हेतु अनुदान (राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा पोषित)		
00-		
20- सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	30000	294
योग:-	30000	294

(₹ दो लाख चौरान्बे हजार मात्र)

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-252(P)/XXVII-4/2010 दिनांक 29 सितम्बर, 2010 में प्राप्त सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

/  
(मंजुल कुमार जोशी)  
अपर सचिव।

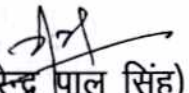


संख्या:-13730/XIV-1/2010, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. प्रबन्ध निदेशक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नई दिल्ली को इस अनुरोध सहित प्रेषित कि अवमुक्त धनराशि की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
3. अपर निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तराखण्ड।
4. वित्त अनुभाग-4/नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
5. जिलाधिकारी, बागेश्वर, चम्पावत, रुद्रप्रयाग एवं उत्तरकाशी, उत्तराखण्ड।
6. जिला सहायक निबन्धक, सहकारी समितियां, बागेश्वर, चम्पावत, रुद्रप्रयाग एवं उत्तरकाशी, उत्तराखण्ड।
7. वरिष्ठ कोषाधिकारी, अल्मोड़ा, उत्तराखण्ड।
8. क्षेत्रीय निदेशक, एन0सी0डी0सी0, क्षेत्रीय कार्यालय, फरेण्डस इन्कलेव, पो0 ओ0 डिफेन्स कालोनी, विधान सभा मार्ग देहरादून।
9. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. प्रभारी मीडिया सेंटर, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर।
11. निजी सचिव, मा0 मंत्री, सहकारिता को मा0 मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
12. निजी सचिव-सचिव, सहकारिता, उत्तराखण्ड शासन।
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

  
(वीरेन्द्र पाल सिंह)  
उपसचिव।